

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 816

बुधवार, 07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

ओएनडीसी

816. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) हाल ही में आरम्भ की गई ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के संबंध में सरकार की उपलब्धियों और नीति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) ई-कॉमर्स के खुले नेटवर्क को अपनाने से छोटे व्यापारियों के किस प्रकार सशक्त होने की संभावना है;
- (ग) क्या सरकार का छोटे व्यापारियों के लाभ हेतु स्थानीय ग्राहकों की सक्रिय भागीदारी को सुकर बनाने का विचार है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) : ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की पहल के तहत धारा 8 की कंपनी है, जिसका उद्देश्य डिजिटल अथवा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है।

अब तक की ओएनडीसी की उपलब्धियां:

- ओएनडीसी नेटवर्क दो श्रेणियों (एफ एंड बी और किराना) के साथ शुरू हुआ और यह मोबिलिटी, फैशन, सौंदर्य और पर्सनल केयर, घर और रसोई, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण, स्वास्थ्य और आरोग्य और बी2बी जैसी अन्य श्रेणियों में इसका विस्तार हुआ है।
- ओएनडीसी पर नेटवर्क भागीदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है क्योंकि इस नेटवर्क पर कई विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है।
- विक्रेता और सेवा प्रदाता 540 से अधिक शहरों में फैले हुए हैं, जो ओएनडीसी नेटवर्क के भौगोलिक कवरेज का विस्तार कर रहे हैं।
- जिन विक्रेताओं को पहली बार डिजिटाइज किया जा रहा है, उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। "फर्स्ट-टाइम डिजिटल" विक्रेताओं को ओएनडीसी नेटवर्क का हिस्सा बनने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न स्कीमों की योजना बनाई जा रही है और उन्हें लागू किया जा रहा है।
- ओएनडीसी एफपीओ और किसानों को इसके नेटवर्क में शामिल करने के लिए

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा नाबार्ड जैसी संस्थाओं के साथ काम कर रहा है।

- ओएनडीसी, सिडबी जैसे परिवेश भागीदारों की सहायता से विभिन्न एसएचजी, सामाजिक क्षेत्र के विक्रेताओं और सूक्ष्म उद्यमियों को ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
- ओएनडीसी, एमएसएमई को इसका लाभ उठाने में सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना तैयार करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के साथ भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। वर्तमान में, विभिन्न एमएसएमई मौजूदा ओएनडीसी विक्रेता ऐप के माध्यम से ओएनडीसी नेटवर्क से जुड़ रहे हैं।

सरकार का उद्देश्य ओएनडीसी को बढ़ावा देने का है, जो भारत में डिजिटल कॉमर्स को सर्वसुलभ बनाने के प्रयोजन से अपनी तरह की पहली वैश्विक पहल है। सरकार का प्रयास वस्तुओं एवं सेवाओं के कुशल आदान-प्रदान को संभव बनाते हुए बड़े एवं लघु उद्यमों को समान स्तर पर लाना तथा उन्हें समान अवसर प्रदान करना है।

(ख) :

ई-कॉमर्स के लिए एक ओपन नेटवर्क को अपनाने से छोटे व्यापारियों को कई प्रकार से सुदृढ़ बनाया जा सकता है:

- छोटे व्यापारी विशिष्ट प्लेटफॉर्म-केंद्रित नीतियों द्वारा शासित होने के बजाय किसी भी ओएनडीसी-संगत अनुप्रयोग का उपयोग करने में सक्षम होंगे। यह छोटे व्यवसायों/व्यापारियों को नेटवर्क पर खोज योग्य होने और व्यवसाय करने के लिए कई विकल्प प्रदान करेगा।
- ओएनडीसी छोटे व्यापारियों को व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंचने के लिए एक नेटवर्क प्रदान करता है और इस प्रकार उन्हें विकास के अधिक अवसर प्रदान करता है।
- ओएनडीसी उच्च प्रवेश बाधाओं को समाप्त करते हुए छोटे व्यापारियों को समान अवसर उपलब्ध करता है।
- ओएनडीसी सभी आकार, स्थान या डिजिटल स्तर के व्यवसायों को डिजिटल कॉमर्स में आसान भागीदारी प्रदान करता है।
- ओएनडीसी में शामिल होने वाले छोटे व्यापारी, अधिक लोगों तक पहुंच सकेंगे और इससे बाजार में ब्रांड के रूप में स्थापित होने में उन्हें मदद मिलेगी।
- ओएनडीसी, भारत में बिज़नेस में ओवरहेड लागत (जैसे, अधिग्रहण लागत, डिजिटल उपस्थिति लागत) और इन्वेंट्री लागत में कमी के माध्यम से व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है।
- ओएनडीसी नेटवर्क के माध्यम से खोजे जा सकने वाले छोटे व्यापारी, भारत में स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं के व्यापार को बढ़ा सकते हैं, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों के निवेश और उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।
- ओएनडीसी ई-कॉमर्स क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देता है, छोटे व्यापारी तकनीकी प्रगति का लाभ उठा सकते हैं और अपनी क्षमताओं और

प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकते हैं।

- अधिक व्यापार, संपूर्ण डिजिटल वाणिज्य मूल्य श्रृंखला अर्थात् लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, अंतिम-छोर तक वितरण आदि में आर्थिक विकास और आजीविका सृजन के अवसरों में मदद कर सकता है।

(ग) और (घ): जी, हां। सरकार छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने और ओएनडीसी के माध्यम से स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने के महत्व को समझती है। सरकार का, छोटे व्यापारियों के लाभ के लिए, निम्नलिखित उपायों के जरिए स्थानीय ग्राहकों की सक्रिय भागीदारी को सक्षम बनाने का प्रस्ताव है:

- उद्योग संघों और सरकारी विभागों के साथ संयुक्त प्रोत्साहन अभियान चलाना ताकि स्थानीय ग्राहकों को छोटे व्यापारियों की सहायता करने और ओएनडीसी नेटवर्क पर उपलब्ध नजदीकी दुकानों से अपेक्षित सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- छोटे व्यापारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन, जो उन्हें अपनी डिजिटल मौजूदगी, विपणन रणनीतियों और बेहतर ग्राहक सेवा की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। यह उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ा सकता है और अधिक स्थानीय ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है।
- ओएनडीसी अकादमी और ओएनडीसी सहायक के माध्यम से उपभोक्ताओं को ओएनडीसी के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्थानीय व्यवसायों की सहायता करने के लाभों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर उनके पसंद के प्रभाव के बारे में बताना।
- छोटे व्यापारियों और ग्राहकों के लिए सुचारु ई-कॉमर्स लेनदेन की सुविधा के लिए विश्वस्तरीय इंटरनेट कनेक्टिविटी, सुरक्षित नेटवर्क और भुगतान गेटवे, स्वचालित शिकायत निवारण तंत्र और अंतिम-छोर वितरण सुविधाओं सहित मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में निवेश।
- ओएनडीसी सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के विभिन्न विभागों के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। राज्य स्तरीय कार्य योजनाओं में तेजी लाने के लिए प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। देशभर में विभिन्न ओएनडीसी जागरूकता अभियान और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।
